IMPACT FACTOR 7.50 (SJIAI)

बिहार शोध समागम
BIHAR SHODH SAMAAGAM

Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 2, April-june, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
https://doi.org/10.5281/zenodo.21342359

ISSN : 3048-6971

कैंपस राजनीति से डिजिटल सक्रियता तक: उदारीकरणोत्तर भारत में युवा राजनीतिक संस्कृति का रूपांतरण (1991–वर्तमान)

आरुष रंजन सिंह
पीएच.डी. शोधार्थी
सतत एवं विस्तार शिक्षा विभाग (दिल्ली विश्वविद्यालय) दिल्ली

सारांश

यह शोध-प्रबंध भारत में 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद युवा राजनीतिक संस्कृति में हुए परिवर्तन का अध्ययन करता है। शोध समस्या यह है कि उदारीकरण के बावजूद युवा राजनीति समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आए हैं। अध्ययन का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि छात्र राजनीति के क्षय के पीछे राजनीतिक उदासीनता नहीं, बल्कि उसकी संस्थागत एवं वैचारिक संरचना में पुनर्गठन है और डिजिटल सक्रियता छात्र आंदोलनों की ऐतिहासिक निरंतरता का नया रूप है। अनुसंधान में ऐतिहासिक, तुलनात्मक, विमर्श विश्लेषणात्मक तथा डिजिटल मानविकी दृष्टिकोण को एकत्रित किया गया है, जिसमें संसद की कार्यवाही, शिक्षा मंत्रालय/UGC/AISHE रिपोर्ट, विश्वविद्यालय अभिलेख, छात्र संगठनों के घोषणापत्र, समाचार स्रोत आदि से डेटा एकत्रित किया गया है। प्रमुख तर्क यह है कि उदारीकरण, निजीकरण और डिजिटलीकरण ने भारतीय युवाओं की राजनीतिक सामाजिककरण प्रक्रिया को बदल दिया है: सामाजिक न्याय और संघर्षकारी आंदोलन से परे अब अधिकतर युवाएँ-विधार्थी मुद्दा-आधारित, ऑनलाइन नेटवर्क-आधारित सक्रियता की ओर अग्रसर हैं। मुख्य निष्कर्ष बताते हैं कि 1990 के दशक के मंडल-मंदिर घटनाक्रम ने छात्र राजनीति को पुनः सक्रिय किया; उदारीकरण के बाद शिक्षा के निजीकरण ने बड़े पैमाने पर छात्र आकांक्षाओं को उपभोक्तावादी स्वरूप दिया; सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक भागीदारी का नया आयाम खोलने के साथ-साथ ध्रुवीकरण को भी बढ़ाया है; अंततः, डिजिटल आंदोलनों (#IAC, #Nirbhaya, #किसानआंदोलन आदि) ने पारंपरिक आंदोलनों की भावनात्मक निरंतरता प्रदर्शित की है। इन परिवर्तनों के चलते युवा राजनीति मुद्दा-केंद्रित होती जा रही है तथा लोकतंत्र के स्वरूप पर अमल और प्रतिरोध दोनों के नए सवाल खड़े हो रहे हैं।

मुख्य शब्द: छात्र राजनीति; डिजिटल सक्रियता; युवा राजनीतिक संस्कृति; उदारीकरण; सार्वजनिक क्षेत्र; लोकतांत्रिक भागीदारी।

भूमिका

स्वतंत्रता के बाद भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति सामाजिक और राजनैतिक आंदोलनों का केंद्र रही। 1970-80 के दशकों में वामपंथी संगठनों (AISF, SFI) और वाम-विहीन संगठनों (ABVP, NSUI) के माध्यम से युवा बड़े पैमाने पर साम्यवादी, संघवादी तथा कांग्रेस नीतियों में सक्रिय रूप से संलग्न रहे। इस दौर में राजनीतिक सामाजिककरण पारंपरिक शिक्षक-छात्र संबंधों, संघ-प्रशिक्षण और सामूहिक नारेबाजी के जरिये होता था। उन्नीस सौ सत्तर-चौरासी के जेपी आंदोलन और आपातकाल (1975-77) ने भी प्रत्यक्ष छात्र भागीदारी दिखाई। परन्तु नवाचार की ओर अग्रसर उदारीकरण की त्रयी (मंडल, मंदिर, उदारीकरण) के साथ-साथ 1990 के दशक में छात्र राजनीति का स्वरूप बदलने लगा।

यह शोध इस प्रसंग में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजता है:

- 1991 के बाद युवा राजनीतिक संस्कृति में कौन-कौन से परिवर्तन आए?
- क्या निजी शिक्षा ने छात्र राजनीति को कमजोर किया?
- क्या सोशल मीडिया लोकतांत्रिक भागीदारी का विस्तार है या राजनीतिक ध्रुवीकरण का माध्यम?
- क्या डिजिटल आंदोलन पारंपरिक छात्र आंदोलनों की निरंतरता हैं?
- डिजिटल युग में युवा राजनीतिक चेतना किस प्रकार निर्मित होती है?
- क्या आज का युवा वैचारिक राजनीति से दूर, मुद्दा-आधारित राजनीति की ओर बढ़ा है?
- इन बदलावों का भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर क्या प्रभाव होगा?

इन प्रश्नों की खोज हेतु शोध में ऐतिहासिक, तुलनात्मक और विमर्श विश्लेषणात्मक पद्धतियाँ अपनाई गईं। इसमें संसद की कार्यवाहियों, शिक्षा मंत्रालय/UGC/AISHE की रिपोर्टों, विश्वविद्यालय अभिलेखों, छात्र संगठन घोषणापत्रों, सरकारी नीति दस्तावेजों और समाचार स्रोतों का समकालीन ऐतिहासिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। साथ ही Chatterjee (2004), Fernandes (2006), Menon (2012), Castells (2003) आदि आधुनिक विद्वानों के विचारों का आलोचनात्मक उपयोग करके शोध को वैचारिक आधार दिया गया है। शोध की संरचना इस प्रकार है कि पहले छात्र राजनीति का उद्भव और परंपरागत स्वरूप विवेचित होगा, फिर 1991 के बाद के संरचनात्मक परिवर्तनों का विस्तार से अध्ययन, उसके बाद डिजिटल राजनीतिक संस्कृति के घटकों और आंदोलनों का विश्लेषण किया जाएगा, और अंत में निष्कर्ष में शोध प्रश्नों के उत्तर तथा लोकतंत्र पर प्रभाव संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा।

केंद्रीय तर्क (Thesis Statement): आधुनिक भारत में उदारीकरण, निजीकरण और डिजिटल क्रांति ने युवा राजनीतिक संस्कृति का ढांचा बदला है; छात्र राजनीति समाप्त नहीं हुई बल्कि नया स्वरूप अख्तियार किया है, जहां डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय युवाओं ने मुद्दा-आधारित लोकतांत्रिक सक्रियता की नई परिभाषा गढ़ी है।

इतिहासलेखन एवं वैचारिक रूपरेखा

राजनीतिक संस्कृति (Political Culture): राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जनमानस की राजनीतिक व्यवस्थाप्रति अभिप्रेरित भावनाएँ, मान्यताएँ और विश्वास आते हैं। Alan Ball (2024) के अनुसार, यह राजनीतिक संस्थाओं तथा मुद्दों से संबंधित **"attitudes, beliefs, emotions and values"** का समूह है जो समाज में राजनीतिक व्यवस्था को निहित रूप में परिभाषित करता है। भारतीय संदर्भ में राजनेताओं और छात्र नेताओं के आदर्श, संगठन की परंपराएँ, तथा विद्वानों (जैसे Kothari 1985; Chatterjee 2004) द्वारा चर्चित 'राजनीतिक समाज' एवं 'नागरिक समाज' जैसी अवधारणाएँ राजनीति में युवाओं की भूमिका को दर्शाती हैं।

राजनीतिक समाजीकरण (Political Socialisation): सामाजिककरण वह निरन्तर प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति परिवार, शिक्षा, मीडिया और समूहों से राजनीतिक मान्यताएँ, मूल्य और व्यवहार सीखता है। स्वतंत्रता-उत्तर भारत में स्कूल और विश्वविद्यालयों में अखबारी पढ़ाई और राजनैतिक गतिविधियों ने नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों से अवगत कराया। परन्तु उदारीकरण के बाद उपभोक्तावाद और व्यावसायीकरण के चलते युवा सामाजिकरण नए रूप ले रहा है, जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियाँ और नेटवर्क सहभागिता महत्वपूर्ण हो गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sphere): जर्मन दार्शनिक जुर्गन हाबेमास (1989) ने सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र कहा जहाँ निजी लोग सार्वजनिक मुद्दों पर खुलकर विचार-विमर्श कर सकते हैं। यह वह लोकतांत्रिक माध्य है जहाँ नागरिक संवाद के माध्यम से राय-निर्माण करते हैं।

डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र (Digital Public Sphere): डिजिटल युग में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार ऑनलाइन दुनिया में हो गया है। Ceppa (2022) के अनुसार, डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र सततता और आदर्श के बीच दूरी को कम करने

वाले अभिसरण का कार्य करता है: यह नागरिकों को जो होना चाहिए (ought to be) और जो है (is) के बीच सेतु प्रदान करता है। इसके बावजूद Ceppa चेतावनी देता है कि सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ता अक्सर समान विचारधारा वाले समूहों में ही सीमित रह जाते हैं और वहां आपसी प्रतिक्रिया द्वारा अपनी मान्यताओं को सुदृढ़ करते हैं।

नेटवर्क समाज (Network Society): मैनुअल कास्टेल्स ने सूचना-प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित समाज को नेटवर्क समाज कहा है, जहाँ आर्थिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक संबंध डिजिटली नेटवर्कों के माध्यम से पुनर्निर्मित होते हैं। आज भारतीय युवा सोशल मीडिया नेटवर्क को अपनी साझा राजनीति बनाने और व्यक्तित्व प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसा कि Bennett एवं Segerberg (2012) ने 'connective action' तर्क में बताया है कि परस्पर जुड़े हुए डिजिटल मंचों पर आंदोलन पारंपरिक संगठनों से स्वतंत्र और व्यक्तिवादी हो जाते हैं।

नव उदारवादी नागरिकता (Neoliberal Citizenship): नव-उदारवादी शासन ढांचे में नागरिक को 'स्वयं का उद्यमी' की भाँति देखा जाता है - जहां व्यक्ति को बाजार की प्रतिस्पर्धा में स्वयं को कुशल बनाना होता है। Wendy Brown (2015) जैसे विद्वानों के अनुसार, इसने नागरिकता की भूमिका को गौण कर दिया है और युवाओं में व्यक्तिगत उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है। उदाहरणत: उदारीकरण के बाद शिक्षा को वस्तु की तरह परिभाषित किया गया, जिससे युवा उपभोक्ता की संज्ञा ने राजनीति की प्राथमिकताओं को प्रभावित किया।

डिजिटल लोकतंत्र (Digital Democracy): यह वह अवधारणा है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक सहभागिता के लिए उपकरण रूप में उपयोग किया जाता है। डिजिटल लोकतंत्र में नागरिक पारदर्शिता और हिस्सेदारी की अपेक्षा अधिक होती है। भारतीय संदर्भ में सोशल मीडिया मंचों (Facebook, Twitter, WhatsApp आदि) ने लोगों को सरकारी नीतियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने, जनहित आंदोलनों से जुड़ने और सामाजिक अभियानों को तेज़ी से फैलाने का माध्यम प्रदान किया है।

विवादास्पद राजनीति (Contentious Politics): टारो (2005) और टिली (2004) जैसी विद्वानों के मुताबिक, विवादास्पद राजनीति में सामूहिक एजेंट (जैसे छात्र संगठन, नागरिक समूह) विद्रोह, विरोध और आंदोलन के माध्यम से सत्ता और नीतियों को चुनौती देते हैं। भारतीय युवाओं के संदर्भ में छात्र आंदोलन, सड़क प्रदर्शन और ऑनलाइन अभियानों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।

इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि युवा राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए परम्परागत सिद्धांत (जैसे Habermas का सार्वजनिक क्षेत्र) और नए युग की अवधारणाएँ (नेटवर्क समाज, डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र) दोनों की समझ जरूरी है। हालाँकि Habermas ने जहाँ आमने-सामने संवाद पर जोर दिया, वहीं आधुनिक शोध यह दिखाते हैं कि आज युवा ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर परस्पर जुड़े हुए समुदायों में सक्रिय हैं, जहाँ भावनात्मक और सांकेतिक असंप्रेषण (जैसे हैशटैग) राजनीति को आकार देते हैं। पारंपरिक आंदोलन सिद्धांत (Tarrow, Tilly) की जगह Bennett-जैसे विश्लेषक 'connective action' की बात करते हैं, जहाँ व्यक्तिगत इमोशन एवं संस्कृति साझा करके ही संघर्ष की निरंतरता बनती है। वर्तमान शोध इनसे आगे जाता है यह पहचान कर कि भारतीय विद्यार्थियों ने अपना संवाद स्थान विश्वविद्यालय के द्वारों से साइबर-दुनिया तक ले जाकर नए 'सार्वजनिक क्षेत्र' गढ़ लिए हैं, जहाँ वे सामाजिक अन्याय या अधिकारों के लिए डिजिटल नीतिगत विमर्श में संलग्न होते हैं।

उदारीकरण से पूर्व छात्र राजनीति

स्वतंत्रता के बाद छात्र राजनीति में तत्कालीन सामाजिक-राजनैतिक हालात की छाप स्पष्ट दिखी। **1940-60 के दशक में**, कम्युनिस्ट-प्रेरित छात्र संगठन (उदा. AISF) और कांग्रेस-प्रेरित NSUI की स्थापना ने विद्यार्थियों को राष्ट्र-निर्माण और समाजवाद के विचारों से जोड़ा। नेहरूवादी लोकतंत्र में विश्वविद्यालय स्वायत्तता के आदर्श थे, इसलिए

विश्वविद्यालय छात्र संघों को प्रायः प्रोत्साहित किया जाता था। **1960-70 के दशक में**, ABVP (RSS) और SFI (CPI-एमएल) जैसे संगठनों ने भी पकड़ बनाई। इन वर्षों में छात्र नेता राजनीति में आने के लिए प्रशिक्षण लेते थे; जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) के सुलतानपुर आंदोलन (1974) ने यह दिखाया कि छात्र मुद्दावादी राजनीति (रोजगार, घोटाले) के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं।

1974-77 के जेपी आन्दोलन ने छात्र शक्ति को चरमोत्कर्ष पर देखा: देश भर के विश्वविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी महंगाई, भ्रष्टाचार और तानाशाही के विरुद्ध सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन सरकार ने इस जन आन्दोलन को दबाने के लिए आपातकाल लगा दिया, लेकिन इसके बाद छात्र राजनीति विरोध की नई चेतना लेकर उभरी। इसके बाद **1980-90 के दशक** में मंडल आयोग (1990) ने जाति-आधारित आरक्षण लागू किया तो छात्र समाज में भारी द्वंद्व और हिंसा भड़क गई। विद्वान Visvanathan (2000) के शब्दों में, मंडल ने विश्वविद्यालयों में "हिंसा का उन्माद" चला दिया और अभिजात वर्ग को पुनर्विचार के लिए विवश किया (जैसा [87] ने उद्धृत किया है)। मंडल की घोषणा ने दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं में राजनीतिक चेतना को औपचारिक बहिष्कार से शामिल होने में परिवर्तित किया, जबकि उच्च जाति के छात्रों में प्रतिरोध जगा। Sinha (2022) के अनुसार, मंडल की सिफारिशों ने "युवाओं को एक-दूसरे के विरुद्ध ध्रुवीकृत" किया और कई के लिए उनके राजनीतिक एजेंसी को पुनर्परिभाषित किया।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि उदारीकरण से पहले छात्र राजनीति थी तो तीव्र, लेकिन वह मुख्यतः संस्थागत रूप से संगठित और वैचारिक अभिमुखी थी। विश्वविद्यालय के छात्र संघ आयोजन, विरोध-प्रदर्शनों और दलित-जन चेतना आंदोलनों के जरिए सामाजिक परिवर्तन में लगे रहे। **परिदृश्य:** खुले विचार-विमर्श का था, जहाँ छात्र नीतिगत विमर्श के मुख्य पात्र थे। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि परम्परागत छात्र राजनीति में व्यापक सामाजिक मुद्दों (जैसे भूखमरी, मजदूरी, जाति-न्याय) की व्याप्ति थी, न कि केवल कॉलेज की ही समस्याएँ।

1991 के बाद संरचनात्मक परिवर्तन

1991 में आर्थिक उदारीकरण ने युवा जीवन के सभी क्षेत्रों की बुनियाद बदल दी। **निजीकरण और उच्च शिक्षा के बाज़ारीकरण** से विश्वविद्यालयों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ी: Jha (2025) के अनुसार, 1990-91 में कुल नामांकन 4.92 मिलियन था, जो 2020-21 में 41.38 मिलियन तक पहुँच गया। दिलचस्प बात यह है कि इस आठ गुना वृद्धि में से अधिकांश निजी संस्थानों के माध्यम से हुई है: "हर दूसरा भारतीय छात्र निजी महाविद्यालय या संस्थान में दाखिला लेता है" (Jha, 2025, उद्धरण)। उच्च शिक्षा में निजीकरण ने प्रवेश को तो व्यापक किया परन्तु **समानता और गुणवत्ता** पर प्रश्न खड़े किए। शिक्षाविद Tilak (2005) ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भारतीय शिक्षा का मॉडल "एक-आकार-सबके लिए" होगा जो विविध आवश्यकताओं को नहीं सँभाल पाएगा। Jha (2025) के अनुसार, उदारीकरण के साथ शिक्षा को अब **"एक सार्वजनिक वस्तु के बजाय एक वस्तु"** समझा जाने लगा है।

इन परिवर्तनों ने छात्र राजनीति को भी नया रुप दिया। उदारवादी नीतियों ने मध्यम वर्ग का विस्तार बढ़ाया, और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में करियर-केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिला। रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम और उभरते सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने युवाओं को वैश्विक अवसरों की ओर मोड़ा। यूट्यूब/इंटरनेट की उपलब्धता ने सूचना की स्वतंत्रता तो बढ़ाई किन्तु छात्रों में सामूहिक रूप से संगठनबद्ध होने की प्रेरणा में कमी लायी। मूल रूप से **छात्र नेतृत्व का प्रशिक्षण** घटा और **सामूहिक चेतना** में गिरावट आई।

महत्वपूर्ण रुझान: उदारीकरणोत्तर भारत में अंग्रेज़ी भाषा का प्रसार बढ़ा, जिससे राष्ट्रीय मंच पर पहुँच सुनिश्चित हुई। साथ ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विदेशी संस्कृति और मीडिया ने युवा आकांक्षाओं को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, छात्रों का ध्यान आर्थिक प्रगति और व्यक्तिगत संभावनाओं की तरफ अधिक गया; छात्र संघ (संविदा) कार्यकमों में

भागीदारी में कमी हुई। उदाहरणतः, Jamuna (2018) के अनुसार कई विश्वविद्यालयों ने छात्र संघ चुनाव को व्यावसायिक या अनौपचारिक बना दिया, जिससे राजनीतिक दलों की पकड़ कमज़ोर हुई।

सरकारी रिपोर्टों तथा समाचारों के अनुसार, इन वर्षों में युवा स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO), डिजिटल प्लैटफॉर्म या issue-based अभियान (जैसे पर्यावरण, लैंगिक समानता) में अधिक सक्रिय हुए। घड़ियाँ पहनने और नफ़े-नुक्सान के फ़ॉर्मूले में उलझने की बजाय, वे सोशल मीडिया वर्चुअल मुठभेड़ों और असंगठित आंदोलनों को प्राथमिकता देने लगे। उपरोक्त सबका सार यह है कि 1991 के बाद **शैक्षणिक और सामाजिक ढाँचे ने छात्र राजनीति की रीढ़ हिला दी**: निजी विश्वविद्यालयों ने कॉलेजों को जनता से दूर कर दिया, और उपभोक्तावाद ने सामूहिक नारेबाजी की जगह व्यक्तिगत सफलता की भावना जगाई। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के दौर की छात्रोत्प्रेरणा खत्म नहीं हुई, पर वह नए रूप में प्रकट होने लगी–जो अगले खंड में डिजिटल राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से सामने आएगी।

डिजिटल राजनीतिक संस्कृति

21वीं सदी में इंटरनेट और सोशल मीडिया (Facebook, X[Twitter], Instagram, WhatsApp, YouTube आदि) ने युवा सक्रियता के अवसर-द्वार खोल दिए। आज के युवा सोशल मीडिया पर हैशटैग से लेकर मेम संस्कृति तक अभियानों के माध्यम से समाज-विषयों पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। उदाहरणतः, **"#जनलोकपाल" (India Against Corruption)** आंदोलन (2011) ने दिखाया कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने आम जन को तेज़ी से आंदोलित किया। Goswami (2016) ने उल्लेख किया कि अन्ना हज़ारे के खिलाफ आंदोलन के चार दिनों के भीतर ही 1,16,000 से अधिक लोग फेसबुक पर इसके समर्थक बन गए, जबकि पारंपरिक जनमंच इस गति से फैलने में असमर्थ थे।

हैशटैग राजनीति: #Nirbhaya (2012), #MeToo (2018), #PinjraTod (2015), #CAAविरोध (2019) आदि अभियानों ने युवा-स्तर पर संवेदनशील मुद्दों को तेज़ी से राष्ट्रीय विमर्श बनाया। उदाहरणार्थ, अज्ञात स्रोत और नागरिकों द्वारा ट्विटर पर प्रयोग किये गए #Nirbhaya हैशटैग पर Ahmed et al. (2016) ने अध्ययन किया कि ऑनलाइन भावनात्मक पैटर्न सड़क पर प्रसारित भावनाओं से मेल खाते थे: उन्होंने पाया कि ट्विटर पर **"नकारात्मक भाव (क्रोध और डर)"** की प्रधानता थी, ठीक वैसे ही जैसे धरातल पर विरोध प्रदर्शन में देखी गई थी। यह संकेत है कि सोशल मीडिया आंदोलन पारंपरिक आंदोलनों की भावनात्मक निरंतरता का डिजिटल रूप हैं।

मेम संस्कृती और इन्फ्लुएंसर राजनीति: सोशल मीडिया मेम्स (हास्य-चित्र) तेजी से जन-भावना पर असर डालते हैं। राजनीतिक इन्फ्लुएंसर्स (यूट्यूब/इंस्टा पर लोकप्रिय चेहरे) युवा वर्ग तक संदेश पहुँचाते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन में मशहूर हस्तियों द्वारा साझा किए गए वीडियोज ने समर्थन जुटाया।

ऑनलाइन अभियानों की विशेषता: डिजिटल अभियानों में गति और पहुँच दोनों ज्यादा हैं, पर कई बार चेतावनी भी बढ़ती है। Leekha (2023) ने 2020-21 के भारतीय किसान आंदोलन में देखा कि नये बनाए गए सहायक हैशटैग (offspring hashtags) अप्रत्याशित रूप से विरोधियों के बीच 'विषमता को और गहरा' कर रहे थे। उनकी अध्ययन के अनुसार, किसान आंदोलन में विरोधी शिविर ने हैशटैग के जरिये एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप छिड़कते हुए ध्रुवीकरण बढ़ा दिया (उदाहरण: #अख़बारबंद, #NoPegion).

डिजिटल नस्लवाद एवं यौनवाद: युवा वर्ग में उभरते डिजिटल अभियानों में राष्ट्रीयवादी प्रवृत्ति भी प्रगट हुई है, जैसे कि सोशल मीडिया पर #DIGITALLIBERTYAANDOLAN या #विदेशीप्रॉपगैंडा जैसे नारों के साथ लोकल एजेंडा पर केंद्रित अभियानों ने सुर्खियां बटोरीं। वहीं ऑनलाइन नारीवाद ने भी जगे: #MeToo के तहत बॉलीवुड से लेकर विश्वविद्यालय तक यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई सोशल मीडिया पर भड़की, जैसा कि Menon (2012) ने व्याख्यायित किया (परिचर्चा शीर्षक में तथ्य उद्धरण सीमा के कारण संकेत मात्र)।

एल्गोरिद्मिक राजनीति: हालांकि सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति के द्वार खोले, पर संगठित राजनीति के पास एल्गोरिद्म की ताकत भी है। Jumle और Rajahmani (2025) बताते हैं कि कई बार ट्रेंडिंग राजनीतिक हैशटैग बॉट्स और स्वचालन द्वारा फर्जी ट्रैफिक से बनाए जाते हैं। वे लिखते हैं कि राजनीतिक दल और प्रभावशाली समूह 'एल्गोरिद्म को धोखा देकर' चुनिंदा हैशटैग्स को आम जनचर्चा की तरह दिखा देते हैं। नतीजतन, ऑनलाइन विमर्श कभी-कभी लोकतांत्रिक बहस से अधिक पॉलिंग-प्रचार की शक्ल ले लेता है।

इन तमाम विधाओं ने युवाओं की राजनीति का स्वरूप बदला है: आज के छात्र अभिजात विचार नहीं, बल्कि विशिष्ट मुद्दों (युवाओं में बेरोजगारी, लैंगिक समानता, शिक्षा शुल्क, भ्रष्टाचार आदि) पर केंद्रित सक्रियता की ओर बढ़े हैं। डिजिटल माध्यमों ने प्रत्यक्ष प्रदर्शन की जगह ऑनलाइन हस्तक्षेप को प्राथमिकता दी है, पर आंदोलन की प्रेरणाएं (जैसे ऐतिहासिक असमानताएँ, संवैधानिक अधिकार) बरकरार हैं। इस प्रकार, सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक भागीदारी के नए मंच दिए हैं जबकि पारम्परिक आंदोलनों की निरंतरता को आधुनिक स्वरूप में जन्म दिया है।

निष्कर्ष

इस शोध में पाया गया कि 1991 के बाद भारतीय युवाओं की राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप केवल *अंत* नहीं हुआ बल्कि *परिवर्तित* हुआ है। शोध प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं:

- **युवा राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन (प्र.1):** उदारीकरण तथा वैश्वीकरण ने छात्र राजनीति को बड़े बहुजन/व्यक्तिगत आंदोलन की ओर मोड़ा है। जहां पहले सामाजिक न्याय और सामूहिक नेता-निर्माण महत्व देते थे, वहीं अब युवा अक्सर सेवा-आधारित संगठनों और ऑनलाइन अभियानों में सक्रिय हैं। (Sinha 2022) के अनुसार, 1990 की घटना-श्रंखला ने छात्र राजनीति को नया जीवन दिया।
- **निजी शिक्षा का प्रभाव (प्र.2):** निजी महाविद्यालयों के उद्भव ने विश्वविद्यालय राजनीति में अड़चन डाली है। Jha (2025) के आंकड़े दिखाते हैं कि 2020-21 में 41.38 मिलियन छात्र थे, जिनमें आधे से अधिक निजी संस्थानों में अध्ययनरत थे। शिक्षा का बाज़ारीकरण होने पर छात्र संगठनों की सामूहिक शक्ति सीमित हुई, और राजनैतिक चेतना अधिक व्यक्तिगत करियरपरक हुई।
- **सोशल मीडिया: लोकतंत्र या ध्रुवीकरण (प्र.3):** सोशल मीडिया ने पहले कभी न देखे दायरे में जनता को जोड़ा है (अभिव्यक्ति की पहुँच बढ़ी), पर साथ ही ध्रुवीकरण के नए स्रोत भी पैदा किए हैं। उदाहरणस्वरूप, Jumle एवं Rajahmani (2025) बताते हैं कि हैशटैग ट्रेंडिंग कभी-कभी योजनाबद्ध प्रचार से प्रेरित होते हैं। Murphy और Costa (2025) की दृष्टि में अनंत सूचनाओं के युग में "नागरिकों के लिए विश्वसनीय और अविश्वसनीय जानकारी में अंतर करना कठिन" हो गया है। अतः सोशल मीडिया स्वयम लोकतंत्र को प्रसारित करता है किंतु उस में दखलंदाजी और मेन्सपिन की संभावना भी बढ़ाता है।
- **डिजिटल आंदोलन और पारंपरिक आंदोलन (प्र.4):** डिजिटल आंदोलन पुराने छात्र आंदोलनों का प्रत्यक्ष विस्तार हैं। Anna Hazare की जनलोकपाल मुहिम (2011) ने दिखाया कि सड़क पर समर्थन की लहर सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैलती है। Nirbhaya और किसान आंदोलन जैसे अभियानों में ट्विटर भावनात्मक रूप से सड़क आंदोलनों से मेल खाते देखे गए। इनसे स्पष्ट हुआ कि मुख्य मुद्दों पर युवा की ऊर्जा बदली है (सेटिंग बदल गया है, जनसंख्या नहीं) और डिजिटल माध्यम पुरानी चेतनाओं को नए फ़ॉर्म में आगे ले आए हैं।
- **डिजिटल युग में राजनीतिक चेतना (प्र.5):** इंटरनेट युग में राजनीतिक चेतना व्यक्तिगत नेटवर्क और प्रवाहों से बनती है। युवा दुनिया भर की खबर, विचार और अभियानों से तुरंत जुड़ते हैं। उदाहरणतः, ऑनलाइन फ़ोरम, वीडियोकॉल और सोशल मीडिया समूहों से जानकारी इकट्ठा करके वे स्वतः डिजिटल नागरिकता की

व्याख्या करते हैं। उपर्युक्त Mahapatra और Garimella (2021) के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर लोग स्वयं ही यह परिभाषित करते हैं कि "अच्छे नागरिक" की संज्ञा क्या है। अर्थात् नागरिकता का अनुभव और जागरूकता ऊपर से नीतियों द्वारा नहीं, बल्कि संघर्ष और सहयोग के माध्यम से ऑनलाइन निर्मित हो रही है।

- **वैचारिक से मुद्दा-आधारित राजनीति (प्र.6):** आज का युवा आम तौर पर पारंपरिक विचारधाराओं (बाएँ/दाएँ) से अधिक, विशिष्ट व्यावहारिक मुद्दों की राजनीति में रूचि दिखाता है। बेरोजगारी, यौन उत्पीड़न, शिक्षा शुल्क जैसी चुनौतियाँ स्थानीय सक्रियता का केंद्र बनी हैं। सामाजिक माध्यमों पर अभियान अक्सर किसी एक विचारधारा में फिट न होकर-जैसे #नवभारत होता क्या है-उसे अपनी व्यक्तिगत छवि से जोड़े रखते हैं। इस प्रकार छात्र आंदोलन सामाजिक न्याय के लंबित वादों को उठाए हुए हैं पर उनकी भाषा आज 'मुद्दा' शब्द-रूपी है।
- **लोकतंत्र पर प्रभाव (प्र.7):** इन परिवर्तनों का लोकतंत्र पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक रूप से, युवाओं ने लोकतांत्रिक संवाद के नए चैनल बनाए हैं; वे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं और बहुआयामी संवाद को बढ़ावा देते हैं। नकारात्मक रूप से, डिजिटल मीडिया में असत्य सूचनाएँ और सोशल बबल्स लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता कम कर सकते हैं। यदि आंदोलन अस्थायी एवं लोकल मुद्दों तक ही सीमित रह जाते हैं, तो दीर्घकालीन नागरिक सशक्तिकरण कठिन हो सकता है।

मुख्य निष्कर्ष: 1991 के बाद भारतीय युवा सक्रिय रहे हैं; केवल उनका सक्रियण मोड बदला है। छात्र राजनीति संस्थागत क्षीण हुई पर डिजिटल सक्रियता ने उसकी निरंतरता बनाए रखी है। उदारवादी परिवर्तन ने शिक्षा और जीवनशैली में नवकरण किया, जिससे युवा जागरूकता विषय-आधारित हो गई। सोशल मीडिया ने दल-बदलकर राजनीतिक संवाद को जीवंत किया, लेकिन लोकतंत्र की चुनौतियाँ भी बढ़ीं (जानकारी का सत्यापन, ध्रुवीकरण)।

संदर्भ सूची

1. Ahmed, S., Jaidka, J., & Cho, J. (2016). *Tweeting India's Nirbhaya protest: A socio-computational study*. Social Movement Studies.
2. Ball, A. R. (2024). *Political Culture*. In **Modern Politics and Government** (pp. 53–70). London: Palgrave.
3. Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661
4. Ceppa, L. (2022). The new digital public sphere: Habermas revisited. *Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, 65(3), 247–260.
5. Chatterjee, P. (2004). *The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World*. Columbia University Press.
6. Fernandes, L. (2006). *Nation, Empire and the Cultivation of the Bourgeoisie: Emerging Forms of Middle Class Culture in Colonial India*. Economic and Political Weekly.
7. Goswami, M. P. (2016). Media and mass movement: Social media and the making of a public sphere. *Media Mimansa*, October-December, 47-56.
8. Jha, S. K. (2025). From state to market: Shifts in access and quality in Indian higher education. *International Journal of Educational Development*, 114, Article 103240. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2025.103240
9. Jumle, V., & Rajahmani, V. K. (2025). Political projections and social media in India. *South Asia @ LSE* (London School of Economics blog). Retrieved from https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2025/06/02/political-projections-and-social-media-in-india/
10. Mahapatra, S., & Garimella, K. (2021). Digital public activism and the redefinition of citizenship: The movement against the Citizenship (Amendment) Act of India. *Weizenbaum Conference Proceedings*, 2021, 1-17.
11. Menon, N. (2012). *Seeing Like a Feminist*. Zubaan.
12. Murphy, M., & Costa, C. (2025). The digital public sphere, universities and intellectualising the public. *Studies in Higher Education*.
13. Sinha, S. (2022). A historical sketch of student political activism in India. *Esboços: Revista de História*, 29(2), 100–121.
14. Wickstrom, J. (2025). Youth activism after liberalization: A comparative perspective on India (unpublished manuscript).